



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 238]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 12, 2004/आश्विन 20, 1926

No. 238]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 12, 2004/ASVINA 20, 1926

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जांच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अक्टूबर, 2004

निर्णायक समीक्षा

विषय : हांगकांग, सिंगापुर और थाईलैंड के मूल के अथवा वहां से निर्यातित पॉलीस्टिरीन पर पाटनरोधी शुल्क लगाने संबंधी निर्णायक समीक्षा की शुरूआत।

सं. 14/8/2004-डीजीएडी.—निर्दिष्ट प्राधिकारी ने वर्ष 1995 में यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 और सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का निर्धारण एवं वसूली और क्षति निर्धारण) नियम 1995 को ध्यान में रखते हुए उपशीर्ष 3903.19 के अंतर्गत आने वाले हांगकांग, सिंगापुर और थाईलैंड (जिन्हें इसके बाद संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित पॉलिस्टिरीन (जिसे इसके बाद संबद्ध वस्तु कहा गया है) के आयातों पर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की थी। प्रारंभिक जांच परिणाम 28 सितम्बर, 1999 की अधिसूचना सं. 33/1/98-डीजीएडी के तहत प्रकाशित किए गए थे और संबद्ध वस्तु पर सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 116/99 -सीमाशुल्क दिनांक 14 अक्टूबर, 1999 के तहत अनंतिम शुल्क लगाया गया था। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने 8 मार्च, 2000 की सं० 33/1/98-डीजीएडी द्वारा अंतिम जांच परिणाम जारी किया था और दिनांक 11 अप्रैल, 2000 की अधिसूचना सं० 42/2000-सीमाशुल्क के अनुसार सीमाशुल्क विभाग द्वारा निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था।

2. विचाराधीन उत्पाद

विचाराधीन उत्पाद पॉलिस्टिरीन है। पॉलिस्टिरीन परिवर्तनशील ताप-सुनम्य रेजिन है जो सामान्य उद्देश्य के क्रिस्टल और इम्पैक्ट ग्रेडों से अत्यंत विशिष्टीकृत रेजिन तक सूत्रीकरण की

व्यापक श्रेणी में उपलब्ध है। पॉलिस्टिरीन विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। यद्यपि, क्रिस्टल पॉलिस्टिरीन, जिसे सामान्य उद्देश्य के पॉलिस्टिरीन (जीपीपीएस) के रूप में जाना जाता है और इम्पैक्ट पॉलिस्टिरीन, जिसे हाई इम्पैक्ट पॉलिस्टिरीन (एचआईपीएस) के रूप में जाना जाता है, वर्तमान जांच का विचारार्थ विषय है। जीपीपीएस एक स्पष्ट, अक्रिस्टलीय पॉलिमर है और इसका उपयोग खाद्य पैकिंग, खाद्य सेवा मर्दों, चिकित्सा संबंधी उत्पादों और ऑडियो कैसेट हेतु पैकेजिंग, कॉम्पैक्ट डिस्क और अन्य उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किया जाता है। एचआईपीएस का उपयोग इम्पैक्ट संशोधनों हेतु पॉलिबुटाडाइन इलास्टोमर्स में किया जाता है और इसका प्रयोग खिलौनों, फर्नीचर, घरेलू सामान, खाद्य पैकेजिंग, खाद्य सेवा, चिकित्सा संबंधी उत्पादों, उपकरणों, बिल्डिंग सामग्री, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हेतु पैकेजिंग में किया जाता है। जीपीपीएस और एचआईपीएस विभिन्न प्रकार के पॉलिस्टिरीन हैं और इसे एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग नहीं किया जा सकता। विस्तार योग्य पॉलिस्टिरीन (जिसे ईपीएस के नाम से जाना जाता है), जो सीमाशुल्क उप-शीर्ष 39031100 के अन्तर्गत वर्गीकृत है, इस जांच के दायरे से बाहर है।

पॉलिस्टिरीन सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की अनुसूची 1 के सीमाशुल्क उपशीर्ष 3903 के अंतर्गत और आईटीसी के 390319 के भीतर वर्गीकृत है। तथापि यह वर्गीकरण संकेतात्मक है और किसी भी प्रकार से वर्तमान जांच के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।

3. जांच शुरूआत

सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम 1995 और इसके अधीन निर्मित नियमों के अनुसार प्राधिकारी को लगाए गए पाटनरोधी शुल्क जारी रखने की जरूरत की समय-समय पर समीक्षा करनी अपेक्षित होती है। प्राधिकारी यह मानते हैं कि सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम 1995 की धारा 9क(5) के प्रावधान के तहत, इस चरण पर सिफारिश किए गए पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा करना उचित होगा। हांगकांग, सिंगापुर और थाईलैंड के मूल की अथवा वहाँ से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं पर लागू पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा की आवश्यकता पर बल देते हुए मै0 पॉलिस्टिरीन उत्पादक एसोसिएशन, मुंबई ने याचिका दायर की है तथा यह अनुरोध किया है कि ऊपर उल्लिखित अधिसूचनाओं के अंतर्गत संबद्ध वस्तु पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क को पांच वर्ष की अवधि के लिए आगे बढ़ाया जाए।

4. शामिल देश

वर्तमान जांच में शामिल देश हांगकांग, सिंगापुर और थाईलैंड (जिन्हें इसके बाद सम्बद्ध देश कहा गया है) हैं।

5. प्रक्रिया

दिनांक 8 मार्च, 2000 की सं0 33/1/98-डीजीएडी द्वारा अधिसूचित अंतिम जांच परिणाम तथा 11 अप्रैल, 2000 की अधिसूचना सं0 42/2000-सीमाशुल्क द्वारा लागू अंतिम शुल्क की समीक्षा करने का निर्णय लेने के पश्चात, प्राधिकारी सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 1995 तथा सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं का अभिज्ञान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं वसूली और क्षति निर्धारण) नियम 1995 के अनुसार सम्बद्ध देश के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित पॉलिस्टिरीन के आयातों के बारे में यह समीक्षा करने के लिए जांच शुरू करते हैं कि क्या पाटनरोधी शुल्क को समाप्त करने से पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा फिर से होने की संभावना है।

इस समीक्षा में 8 मार्च, 2000 की अधिसूचना सं0 33/1/98-डीजीएडी के सभी पहलुओं को शामिल किया गया है। मूल जांच में मै0 पॉलिस्टाइरीन उत्पादक एसोसिएशन, मुंबई ने घरेलू उद्योग

का प्रतिनिधित्व किया था । प्राधिकारी नियमावली के अनुसार आवेदनकर्ता, जो भारत में संबद्ध वस्तु के उत्पादन के बड़े भाग का उत्पादन करते हैं, को घरेलू उद्योग का प्रतिनिधि मानने का प्रस्ताव करते हैं ।

6. जांच की अवधि

वर्तमान समीक्षा के प्रयोजन के लिए जांच की अवधि 1 अप्रैल, 2003 से 31 मार्च, 2004 (12 महीने) तक की है ।

7 सूचना प्रस्तुत करना

संबद्ध देशों के निर्यातकों और भारत में उनके दूतावासों/उच्चायोगों के माध्यम से उनकी सरकारों, ज्ञात संबद्ध आयातकों और उपयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को संबंधित सूचना निर्धारित प्रपत्र में और निर्धारित ढंग से प्रस्तुत करने और अपने विचारों से निम्नलिखित को अवगत कराने के लिए अलग से लिखा जा रहा है ।

निर्दिष्ट प्राधिकारी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय (डीजीएडी), कमरा सं०-243, उद्योग भवन, नई दिल्ली- 110011

अन्य कोई हितबद्ध पार्टी भी नीचे दी गई समयावधि के भीतर निर्धारित प्रपत्र में और निर्धारित ढंग से जांच से संबंधित अनुरोध कर सकती है ।

8. समय सीमा

वर्तमान समीक्षा से संबंधित कोई सूचना तथा सुनवाई के लिए कोई अनुरोध प्राधिकारी को उपर्युक्त पते पर इस समीक्षा अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से चालीस (40) दिनों के भीतर पहुँच जाने चाहिए । यदि निर्धारित समय के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अपूर्ण हो तो निर्दिष्ट प्राधिकारी उपर्युक्त नियमों के अनुसार रिकार्डों में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अपने जाँच परिणाम रिकार्ड कर सकते हैं ।

9. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

नियम 6(7) के अनुसार कोई भी हितबद्ध पार्टी उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकती है जिसमें अन्य हितबद्ध पार्टियों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के अगोपनीय अंश रखे गए हैं । यदि कोई हितबद्ध पार्टी आवश्यक सूचना जुटाने से मना करती है या उचित समय के भीतर उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराती है या जांच में अत्यधिक बाधा डालती है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकता है तथा केन्द्रीय संस्कार को यथोचित सिफारिशें कर सकता है ।

अभिजित सेनगुप्त, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 12th October, 2004

SUNSET REVIEW

Subject : Initiation of Sunset Review regarding anti-dumping duty imposed on Polystyrene originating in or exported from Hong Kong, Singapore and Thailand.

No. 14/8/2004-DGAD.— The Designated Authority, having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Duty or Additional Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, recommended imposition of provisional Anti Dumping duty on imports of Polystyrene (hereinafter referred to as subject goods) originating in or exported from Hong Kong, Singapore and Hong Kong (referred to as subject countries) falling under Sub-heading 3903.19. The preliminary findings were published vide Notification No. 33/1/98-DGAD dated 28th September 1999 and provisional duty was imposed on the subject goods vide Customs notification No. 116/99-Customs dated 14th October 1999. The Designated Authority came out with final findings on 8th March 2000 vide No. 33/1/98-DGAD and definitive anti dumping duty was imposed by Customs as per notification No. 42/2000-Customs dated 11th April 2000.

2. Product Under Consideration

The product under consideration is Polystyrene. Polystyrene is a versatile thermoplastic resin available in wide range of formulation from general purposes crystal and impact grades to highly specialized resins. Polystyrene can be of various forms. However, crystal polystyrene popularly known as General Purposes Polystyrene (GPPS) and impact polystyrene popularly known as High Impact Polystyrene (HIPS) are the subject matter of the present investigation. GPPS is a clear, amorphous polymer and finds application in food packaging, food service items, medical care products, and packaging for audio cassettes, compact discs, and other consumer electronic media. HIPS makes use of polybutadiene elastomers for impact modifications and finds

applications in toys, furniture, housewares, food packaging, food service, medical care products, appliances, building materials, consumer electronics, and packaging for electronic media. GPPS and HIPS are different types of polystyrenes and are not substituted with each other. Expansible Polystyrene (popularly known as EPS) classified under custom sub-heading 39031100, is beyond the scope of the investigation.

Polystyrene is classified under custom sub-heading 3903 of Schedule 1 of the customs Tariff Act, 1975 and within 390319 of the ITC. The classification is, however, indicative and in no way binding on the scope of the present investigations.

3. Initiation

The Customs Tariff (Amendment) Act 1995 and the rules made there under require the Authority to review from time to time the need for continuance of anti dumping duty. The Designated Authority considers that the sunset review of the Anti-Dumping Duty recommended would be appropriate at this stage under the provision of section 9A (5) of the Customs Tariff (Amendment) Act, 1995 as amended. M/s. Polystyrene Producers' Association, Mumbai, have filed a petition substantiating the need for sunset review of the antidumping duty imposed on the subject goods originating in or exported from Hong Kong, Singapore and Thailand and have requested to continuation of the anti-dumping duty imposed on subject goods under the above mentioned notifications for a further period of 5 years.

4. Countries Involved:

The countries involved in the present investigations are Hong Kong, Singapore and Thailand (referred to as subject countries hereinafter).

5. Procedure

Having decided to review the final findings notified vide No. 33/1/98-DGAD dated 8th March 2000 and final duty imposed by Notification No 42/2000-Customs dated 11th April 2000, the Authority hereby initiates investigations to review whether cessation of antidumping duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury on imports of polystyrene originating in or exported from subject countries, in accordance with the Customs Tariff (Amendment) Act, 1995 and the Customs Tariff

3072 GF/04 - 2

(Identification, Assessment & Collection of Anti Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995.

The review covers all aspects of Notification No.33/1/98-DGAD dated 8th March 2000. M/s. Polystyrene Producers' Association, Mumbai represented the domestic industry in the original investigations. The Authority proposes to consider the applicant who constitutes the major proportion of the production of the subject goods in India to represent the domestic industry in accordance with the Rules supra.

6. PERIOD OF INVESTIGATION

The period of investigation for the purpose of the present review is 1st April 2003 to 31st March 2004 (12 months).

7. Submission of Information:

The exporters in subject country, their government through their Embassy/High Commission in India, the importers and users in India known to be concerned and the domestic industry are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the:

The Designated Authority, Ministry of Commerce & Industry, Department of Commerce, Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties, (DGAD), Room No. 243, Udyog Bhavan, New Delhi-110011

Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.

8. Time Limit

Any information relating to the present review and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 Days) from the date of publication of this review notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Designated Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules supra.

9. Inspection of Public File:

In terms of Rules 6(7), any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

ABHIJIT SENGUPTA, Designated Authority